

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

वर्ष 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि में गिरावट देखी है। इस वर्ष के आरंभ में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और वस्तुओं की कीमतों में तीव्र बढ़ोतरी और इस वर्ष के उत्तरार्ध में वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न वैश्विक मंदी आने के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट हुई। वैश्विक संकट का प्रभाव पूंजी प्रवाहों, वित्तीय बाजारों और व्यापार की सरणियों के माध्यम से महसूस किया गया। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (उपादान लागत पर) की वृद्धि 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान 9.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में 2008-09 में गिरकर 6.7 प्रतिशत रह गई। फिर भी, भारत कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वैश्विक संकट में अधिक लोचशील रहा है। 2007-08 में लगभग 37.7 प्रतिशत की बचत दर और 39.1 प्रतिशत की पूंजी निर्माण दर से समर्थित घरेलू अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों से इसकी हाल की वृद्धि के अनुमानों से अर्थव्यवस्था के विकास को पुनरुज्जीवित करने की संभावना है। आर्थिक पुनरुज्जीवन को अधिक महत्व दिए जाने से आर्थिक मंदी के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रति-चक्रीय राजकोषीय उपायों के कारण एफआरबीएम लक्ष्यों से अस्थायी विपथन हुआ है।

1. आर्थिक विकास

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 2008-09 के संशोधित अनुमान जारी किए हैं। उपादान लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 2008-09 के दौरान 33.39 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है जो 2007-08 में 9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 में 6.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। 2008-09 में वृद्धि में गिरावट मुख्यतया 2007-08 में उद्योग में तीव्र गिरावट के कारण हुई जो 8.1 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत पर आ गई। उद्योग के भीतर, विनिर्माण, बिजली, गैस और जलापूर्ति तथा निर्माण कार्यकलापों में तीव्र गिरावट हुई जबकि खनन और उत्खनन क्षेत्रों ने मामूली वृद्धि दर्शायी है। कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन में वृद्धि 2007-08 में 4.9 प्रतिशत से गिरकर 1.6 प्रतिशत पर आ गई है। सेवा क्षेत्र के विकास में मंदी कम हुई थी। यह 2007-08 में 10.9 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 9.7 प्रतिशत अनुमानित है। सेवा क्षेत्र का घटकवार विश्लेषण दर्शाता है कि “व्यापार, होटल, परिवहन और संचार” में वृद्धि में गिरावट हुई जो 2007-08 में 12.4 प्रतिशत से 2008-09 में 9 प्रतिशत पर आ गई जबकि “वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और व्यवसाय सेवाओं” के मामले में यह वृद्धि 2007-08 में 11.7 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 7.8 प्रतिशत पर आ गई है। इन सेवाओं में गिरावट के प्रभाव को “सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं” के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि द्वारा थोड़ा सुखद बना दिया गया, जो 2007-08 में 6.8 प्रतिशत से 2008-09 में 13.1 प्रतिशत हो गई। इस वृद्धित विकास का श्रेय वैश्विक मंदी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय नीति के अनुरूप सरकारी व्यय में बढ़ोतरी को दिया जा सकता है।

मांग पक्ष से वृद्धि का विश्लेषण इंगित करता है कि निजी उपभोग वृद्धि 2007-08 में 8.5 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 2.9 प्रतिशत पर आ गई, जबकि नियत पूंजी निर्माण में वृद्धि 2007-08 में 12.9 प्रतिशत से गिरकर 2008-09 में 8.2 प्रतिशत रह गई और ऐसा मोटे तौर पर वैश्विक मंदी का घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव के कारण हुआ था। निजी उपभोग तथा पूंजी निर्माण की वृद्धि में आई गिरावट को सरकारी उपभोग की वृद्धि में बढ़ोतरी, जो 2007-08 में 7.4 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 20.2 प्रतिशत हुई, ने आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया है। इसके परिणामस्वरूप बाजार मूल्यों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2007-08 में 9.1 प्रतिशत के मुकाबले 2008-09 में 6.1 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(क) कृषि उत्पादन

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 2007-08 (अंतिम अनुमान) में हुए 230.78 मिलियन टन के मुकाबले 2008-09 में 229.85 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है। खरीफ (2008-09) के दौरान बुआई क्षेत्र 1014.81 लाख हेक्टेयर था जो पिछले वर्ष के बुआई क्षेत्र से 2.3 प्रतिशत कम है। 1.5.2009 को मिली सूचना के अनुसार रबी (2008-09) के दौरान 641.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी जो पिछले वर्ष के बुआई क्षेत्र से 2.9 प्रतिशत अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किए गए 2009 के व्यापक मौसम अनुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम की बारिश (जून से सितम्बर) पूरे देश में लगभग सामान्य रहने की संभावना है। तदनुसार, सब कुछ ठीक रहते हुए आगामी वर्ष में कृषि की वृद्धि सामान्य बने रहने की आशा है।

(ख) औद्योगिक उत्पादन

वर्ष 2008-09 (अनंतिम) का औद्योगिक उत्पादन का समग्र सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र में हुई वृद्धि में तीव्र गिरावट दर्शाता है, यह वृद्धि 2007-08 के दौरान 8.5 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई। 2008-09 के दौरान विनिर्माण में हुई वृद्धि मात्र 2.3 प्रतिशत थी, जबकि यह 2007-08 में 9.0 प्रतिशत थी। खनन क्षेत्र में 2008-09 के दौरान 2.3 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 2007-08 के दौरान यह वृद्धि 5.1 प्रतिशत थी। बिजली क्षेत्र में 2007-08 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2008-09 के दौरान 2.8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2008-09 में समग्र रूप से 6 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में हुई वृद्धि 2007-08 में हुई 5.9 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2.7 प्रतिशत थी। कोयला और सीमेंट की वृद्धि दर क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत थी। इस वर्ष के दौरान परिष्कृत कार्बन इस्पात में केवल 0.4 प्रतिशत तथा पेट्रोलियम उत्पादों में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2007-08 में उनकी वृद्धि से कम है। कच्चे तेल के उत्पादन में 2008-09 के दौरान 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ग) मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में हुई घट-बढ़ द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर मापित मुद्रास्फीति 2 अगस्त 2008 के 12.9 प्रतिशत के अपने अंतर-वर्ष शीर्ष से तेजी से कम होती हुई 28 मार्च 2009 तक 0.8 प्रतिशत पर आ गई। औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 2007-08 में 4.7 प्रतिशत के मुकाबले 2008-09 में 8.4 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष (2009-10) की शुरुआत में अप्रैल, 2009 के प्रथम सप्ताह की स्थिति के अनुसार मुद्रास्फीति 0.8 प्रतिशत के स्तर पर थी और मई 2009 समाप्त होने तक 1 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही। 20 जून, 2009 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के तदनु रूप सप्ताह के दौरान 11.91 प्रतिशत की तुलना में (-)1.3 प्रतिशत थी। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति में वर्षानुवर्ष आधार पर एक वर्ष पूर्व मौजूद 7.9 प्रतिशत के स्तर से मार्च 2009 में 8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

II वैदेशिक क्षेत्र

वर्ष 2008-09 के लिए आरंभ में 200 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य रखा गया था। जिसे बाद में परिशोधित करके 175 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया। 2008-09 में, वैश्विक मंदी के बावजूद, पण्य-निर्यात 3.6 प्रतिशत की संवृद्धि के साथ 168.7 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया और इस प्रकार संशोधित निर्यात लक्ष्य का 96.4 प्रतिशत प्राप्त किया। यद्यपि, अगस्त 2008 तक निर्यात संवृद्धि सशक्त थी, वैश्विक मंदी के कारण यह सितंबर में कम हो गई और अक्टूबर 2008 से मार्च 2009 तक यह ऋणात्मक हो गई। यह ऋणात्मक प्रवृत्ति अप्रैल 2009 में जारी रही जब निर्यात संवृद्धि (-)33.2 प्रतिशत थी। 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान निर्यातों के प्रमुख प्रेरक इंजीनियरी वस्तुएं और रसायन तथा संबंधित उत्पाद हैं। पेट्रोलियम और वस्त्र निर्यातों में घनात्मक किंतु धीमी वृद्धि देखी गई, जबकि हस्तशिल्प, प्राथमिक उत्पादों तथा रत्नों और आभूषणों के निर्यातों ने ऋणात्मक संवृद्धि दर्ज की। 2008-09 के दौरान, आयात संवृद्धि पीओएल और पीओएल-भिन्न आयातों, दोनों के क्रमशः 16.9 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत पर सामान्य होने से 14.4 प्रतिशत पर अवमंदित थी। सोना और चांदी के आयातों ने (-)7 प्रतिशत की ऋणात्मक संवृद्धि दर्ज की तथा पीओएल-भिन्न सर्राफा-भिन्न आयात 15 प्रतिशत बढ़े। ऐसा वैश्विक मंदी के कारण था, जो कमतर ईंधन कीमतों, जिसमें ब्रेंट कीमत में केवल 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कच्चे तेल के विविध समूहों का भारतीय आयात 4 प्रतिशत बढ़ा; औद्योगिक कार्यकलापों में मंदी और निर्यातों के लिए कम मांग के फलस्वरूप जिससे निर्यातों और औद्योगिक कार्यकलाप के लिए आवश्यक आयातों की मांग कम हो गई। आयात संवृद्धि में निर्यात संवृद्धि से एक माह के अंतराल से अक्टूबर 2008 से गिरावट शुरू हुई, और यह जनवरी से मार्च 2009 में ऋणात्मक भी हो गई। यह ऋणात्मक प्रवृत्ति अप्रैल 2009 में भी जारी रही जब आयात संवृद्धि (-)36.6 प्रतिशत पर थी। जबकि तेल की आयात संवृद्धि 58.5 प्रतिशत पर कम थी, तेल-भिन्न आयात संवृद्धि अप्रैल 2008 में 24.6 प्रतिशत पर कमतर थी। व्यापार घाटा 2007-08 में 88.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर (सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार) 2008-09 में 119.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

(क) सेवा निर्यात

वैश्विक मंदी का प्रभाव दिसंबर, 2008 तक भारत के सेवा निर्यातों पर सापेक्षतया कम था, यद्यपि सेवा निर्यात संवृद्धि दर अप्रैल-दिसंबर, 2008-09 के दौरान 16.3 प्रतिशत पर सामान्य हो गयी। इस अवधि के दौरान बीमा क्षेत्र में (-)8.2 प्रतिशत की ऋणात्मक संवृद्धि दर और यात्रा सेवाओं में 6.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर पर तीव्र गिरावट दर्ज की गई। यहां तक कि परिवहन सेवाओं और विविध सेवाओं में भी कमतर संवृद्धि दर्ज की गई। साफ्टवेयर सेवाओं में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वैश्विक वित्तीय संकट और विश्व वित्तीय सेवा निर्यातों की संवृद्धि दर में गिरावट के बावजूद वित्तीय सेवाओं में 45.7 प्रतिशत की सशक्त संवृद्धि दर्ज की गई। तथापि व्यावासायिक सेवाएं 3.9 प्रतिशत की कम दर पर बढ़ी।

अप्रैल-दिसंबर 2008-09 में वास्तुकला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी सेवाओं के आयात में गिरावट और व्यवसाय तथा प्रबंधन परामर्शदात्री सेवाओं के आयात में सापेक्षतया कम संवृद्धि के कारण व्यवसाय सेवा आयातों (जैसाकि व्यवसाय सेवा निर्यातों के मामले में) की संवृद्धि दर में तीव्र गिरावट हुई। यात्रा सेवाओं की आयात संवृद्धि तीव्रता से घटकर 5.9 प्रतिशत हो गई, जबकि परिवहन आयात संवृद्धि में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई, यद्यपि यह सामान्य होकर 26.5 प्रतिशत रह गई।

(ख) भुगतान संतुलन (बीओपी) और व्यापार घाटा

अगस्त, 2007 के आस-पास आरम्भ हुए वैश्विक वित्तीय संकट ने पूंजीप्रवाहों में मन्दन के द्वारा भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। यह प्रभाव विशेष रूप से सितम्बर, 2008 से मुखर हुआ, जब लेहमन ब्रदर्स के पतन से आरम्भ हुई अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताएं बढ़ गईं। अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल और विश्व के उन्नत देशों में वास्तविक आर्थिक क्रियाकलाप में मन्दी उभरती अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह में उलटफेर होने और इन अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात के लिए मांग में कमी में परिलक्षित हुई। भारत का विदेशी क्षेत्र भी व्यापार और वित्तीय माध्यमों के द्वारा प्रवाहित हुआ और वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश में कमी के संदर्भ में और वर्ष 2008-09 के दौरान निर्यात वृद्धि में कमी के संदर्भ में वैश्विक घटनाक्रम का प्रभाव होते हुए भी देश के विदेशी क्षेत्र ने लचीलापन दर्शाया है क्योंकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह अप्रैल-दिसंबर, 2008 के दौरान अधिक रहे और प्रेषणों तथा साफ्टवेयर निर्यातों के रूप में अधिक अदृश्य (अप्रत्यक्ष) प्राप्ति हुई जिसने अधिक व्यापार घाटे के प्रभाव को प्रतिशतित कर दिया। सितंबर, 2008 से तेल की कीमतों में गिरावट ने भी 2008-09 के दौरान तेल आयात वृद्धि दरों को कम रखने में योगदान दिया। विदेशी मुद्रा भण्डार की अच्छी स्थिति से भी घरेलू विदेशी मुद्रा बाजारों में नकदी संबंधी प्रतिकूल विदेशी क्षेत्र का घटनाक्रम के प्रभाव और परिणामी रूप से भारतीय रुपये की विनियम दर में उतार-चढ़ाव को कम करने में सहायता मिली है।

अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान व्यापार घाटा जो विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 69.3 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 8.2 प्रतिशत) से बढ़कर 105.3 बिलियन अमरीकी डालर (सं.घ.उ. का 12 प्रतिशत) हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान अदृश्य मदें (निवल) 2007-08 की इसी अवधि के दौरान 53.8 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 6.4 प्रतिशत) की तुलना में 68.9 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 7.8 प्रतिशत) पर 28 प्रतिशत अधिक थी। अप्रैल-दिसंबर 2007 के दौरान 15.5 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत) की तुलना में चालू खाता घाटा अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान 36.5 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 4.1 प्रतिशत) पर काफी अधिक था।

भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में, निवल पूंजी प्रवाह अप्रैल-दिसंबर 2007 के दौरान 82.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान 15.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा। जबकि अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का निवल आगम 27.4 बिलियन अमरीकी डालर था जो इसके पूर्व वर्ष के 20.0 बिलियन डालर के स्तर से अधिक बना रहा, उसी अवधि के दौरान पोर्टफोलियो निवेश (निवल) में 11.3 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया (अप्रैल-दिसंबर 2007 के दौरान 33.3 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह)। वस्तुतः विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश के संबंध में निवल बहिर्प्रवाह भी अप्रैल-दिसम्बर 2007 के दौरान 24.5 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अंतर्वाह की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान 12.4 बिलियन अमरीकी डालर पर और अधिक रहा। अनिवासी भारतीय जमाराशि ने भी उलटफेर दर्शाया जो अनिवासी भारतीय जमाराशि पर ब्याज दरों में उर्ध्वमुखी संशोधन द्वारा बढ़ोतरी के प्रभाव का द्योतक है। विदेशी वाणिज्यिक उधार और अल्पावधिक व्यापार ऋण (निवल) प्रवाह ने अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव को प्रतिबिम्बित किया। परिणास्वरूप नकदी की कमी हुई निजी क्षेत्र के लिए वित्त साधन की उपलब्धता कम हो गई। अक्टूबर दिसम्बर 2008 के दौरान पूंजी खाता शेष -3.7 बिलियन अमरीकी डालर पर नकारात्मक था जबकि अक्टूबर-दिसम्बर 2007 के दौरान पूंजी खाते में 31.0 बिलियन अमरीकी डालर का अधिशेष था।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में अब तक वैदेशिक क्षेत्र का घटनाक्रम विदेशी संस्थागत निवेशकों से पूंजी प्रवाह के संदर्भ में सुधार दर्शाता है जो बाजार के क्रियाकलापों का पुनुरोत्कर्ष तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के बढ़े हुए विश्वास को परिलक्षित करता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-मई 2009 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इक्विटी और ऋण लिखतों में कुल मिलाकर 5.4 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार भी मार्च 2009 के अंत में 252.0 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़कर 29 मई 2009 को 262.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार जिसमें विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए), स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और रिजर्व ट्रांश पोजीशन (आरटीपी) शामिल हैं, मई 2008 के अंत में 314.6 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। प्रारक्षित भंडार उसके बाद नवम्बर 2008 के अन्त में घटकर 247.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया और मार्च 2009 के अन्त में 252.0 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। तथापि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह 29 मई, 2009 को बढ़कर 262.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

विदेशी मुद्रा आस्तियां 31.3.2008 को 299.2 बिलियन अमरीकी डालर से 57.8 बिलियन अमरीकी डालर घट कर 31.3.2009 को 241.4 बिलियन अमरीकी डालर रह गईं; इस गिरावट का कारण मुख्यतया मूल्यन परिवर्तन था, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के सुदृढीकरण के प्रभाव को परिलक्षित करता है। तथापि, देश की विदेशी मुद्रा आस्तियां 29 मई, 2009 को बढ़कर 251.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में रुपया विनिमय दर और मुद्रा अस्थिरता में तीव्र गिरावट देखने को मिली। प्रति अमरीकी डालर रुपए की विनिमय दर जो मार्च 2008 के अंत में 39.99 रुपए प्रति अमरीकी डालर थी, में अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान उतार और चढ़ाव दोनों दिखाई दिए परन्तु सितम्बर 2008 से इसमें और मूल्यह्रास होकर 5 मार्च, 2009 को यह 52.09 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गई। 2008-09 के दौरान प्रति अमरीकी डालर रुपए की विनिमय दर में 31 मार्च, 2008 के इसके स्तर की तुलना में 21.5 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ। लेकिन मार्च अंत 2009 में यह सुधरकर 50.95 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया। वर्तमान वर्ष 2009-10 में, हालांकि रुपए की विनिमय दर में 31 मार्च, 2009 को 50.95 रुपए प्रति अमरीकी डालर से 7.8 प्रतिशत का अधिमूल्यन होकर 10 जून, 2009 को यह 47.27 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया।

III मौद्रिक घटनाक्रम

वर्ष 2008-09 में मौद्रिक नीति संबंधी परिदृश्य में वर्ष के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बीच एक विरोधाभास दिखाई दिया क्योंकि इसे स्वयं को उभरती हुई स्थिति के अनुरूप ढालना था।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के पहले छह महीनों में, ऐसी स्थिति देखने में आई जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़े हुए पूंजी अंतर्प्रवाहों के परिणामस्वरूप उत्पन्न मौद्रिक विस्तार को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया; नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) और रेपो रेट में वृद्धियां की गईं। सीआरआर दर जहां 26 अप्रैल 2008 को 7.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 अगस्त, 2008 से 9.0 प्रतिशत की गई, रेपो दर भी 1 अप्रैल 2008 को 7.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 जुलाई, 2008 को 9.0 प्रतिशत कर दी गई। तथापि रिवर्स रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।

बाद के महीनों के दौरान, विदेशी संस्थागत निवेशक अंतर्प्रवाहों में गिरावट के कारण, पूंजी अंतर्प्रवाहों में कमी आ गई जिसमें बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति उलट गई। सितम्बर/अक्तूबर 2008 के महीनों में विरोधाभासी स्थिति देखने को मिली। वैश्विक वित्तीय बाजारों में मच रही उथलपुथल के साथ ही भारतीय मुद्रा बाजार में नकदी की कमी दृष्टिगोचर होने लगी। इस स्थिति के निराकरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपाय जैसे सीआरआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) में कमी करने जैसे विभिन्न उपाय शुरू किए। सीआरआर को 30 अगस्त 2008 को 9.0 प्रतिशत से घटाकर 17 जनवरी, 2009 से 5.0 प्रतिशत किया गया। नकदी के उभरते हुए संकट के परिप्रेक्ष्य में रेपोदर अक्तूबर, 2008 के आरंभ में 9.0 प्रतिशत से कम करके 21 अप्रैल, 2009 से 4.75 प्रतिशत की गयी, जबकि रिवर्स रेपो दर भी 6.0 प्रतिशत (नवम्बर 2008 में प्रचलित दर) से घटाकर 21 अप्रैल, 2009 से 3.25 प्रतिशत की गई। एसएलआर में भी निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) को 25 प्रतिशत से 100 आधार बिन्दुओं की कटौती करके 8 नवम्बर, 2008 से आरम्भ होने वाले सप्ताह से 24 प्रतिशत किया गया। इससे स्थिति में सुधार आया। वर्ष का अंत आते-आते मुद्रा बाजार के प्रतिभागियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की रिवर्स रेपो दर सुविधा में बड़ी मात्रा में धनराशियां रखी होने के कारण स्थिति बदल कर अधिशेष नकदी की स्थिति हो गई।

उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, 2008-09 के पूरे वर्ष के लिए प्रारक्षित मुद्रा (एम₀) में 2007-08 में 31.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। एम₀ के एक महत्वपूर्ण स्रोत अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में पूर्ववर्ती वर्ष में 42.7 प्रतिशत के विस्तार की तुलना में 2008-09 के दौरान 3.6 प्रतिशत की मंद वृद्धि दर्ज हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-22 मई, 2009) के दौरान एम₀ में गत वर्ष की इसी अवधि में 1.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 3.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। स्थूल मुद्रा (एम₃) में 2007-08 में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 के दौरान 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 (अप्रैल-22 मई, 2009) के दौरान अब तक एम₃ में गत वर्ष की इसी अवधि में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

आर्थिक गतिविधियों में निरन्तर उछाल, जिसके परिणामस्वरूप लगातार तीसरे वर्ष (2007-08) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, में 2008-09 के दौरान मंदी आ गई। यद्यपि वर्ष के पूर्वार्ध में वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में अच्छी वृद्धि दिखाई दी, वर्ष के उत्तरार्ध में इसमें विशेष रूप से गिरावट आ गई। 2007-08 के दौरान बैंक ऋण में जहां 22.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, वहीं 2008-09 के दौरान इसमें वृद्धि केवल 17.3 प्रतिशत थी। खाद्य ऋण में 2007-08 में 4.6 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2008-09 के दौरान 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। खाद्य-भिन्न ऋण में 2007-08 में 23.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक (अप्रैल - 22 मई 2009) बैंक ऋण में 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसमें कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई थी। खाद्य भिन्न ऋण में अप्रैल-22 मई, 2009 में 1.9 प्रतिशत दर्ज हुई जबकि 2008-09 की इसी अवधि में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों

द्वारा उनकी निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के प्रतिशत के रूप में सांविधिक नकदी अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश 24 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से अधिक बना रहा। मार्च 2008 के अंत में 27.8 प्रतिशत के स्तर की तुलना में मार्च 2009 के अन्त में इसमें 28.1 प्रतिशत के स्तर तक वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक नकदी अनुपात में 2007-08 के दौरान 14.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मौद्रिक नीति को हाल में देखने में आई मन्द आर्थिक वृद्धि के अनुरूप ढालने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक को 2009-10 के वार्षिक नीति विवरण का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव न्यूनतम करना और अर्थव्यवस्था को मूल्य और वित्तीय स्थिरता के अनुकूल पुनः उच्च विकास के पथ पर ले जाने में सहायता करना है।

IV केन्द्र सरकार की वित्त व्यवस्था

एफआरबीएम लागू होने के बाद की अवधि में, वर्ष 2007-08 तक राजकोषीय सुदृढीकरण के क्षेत्र में प्रगति संतोषजनक रही है। बजट अनुमान 2008-09 में राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से काफी नीचे रखने की परिकल्पना की गई है। तथापि, वैश्विक स्तर पर वस्तुओं (विशेषकर कच्चे पेट्रोलियम) की कीमतों में वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र के पक्ष में व्यय में सुविचारित वृद्धि के कारण अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से निजात पाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण, यह महसूस किया गया कि पहले परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना कठिन हो सकता है। वृहत-अर्थव्यवस्था पर बेहद दबाव के वर्ष में राजकोषीय प्रोत्साहन सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों के अनुरूप है।

केन्द्र के लिए सकल कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, जो पूर्व-एफआरबीएम अवधि में लगभग 8-10 प्रतिशत के बीच में अवरूद्ध रहा, 2006-07 में बढ़कर 11.5 प्रतिशत और 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद का 12.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रवृत्ति की निरन्तरता की परिकल्पना करते हुए 2008-09 के बजट में इसे सकल घरेलू उत्पाद के 13.0 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया। 2008-09 के लिए लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए केन्द्र सरकार के लेखा विवरणों में (अन्तिम वास्तविक) केन्द्र की सकल कर प्राप्तियों में वृद्धि 2007-08 के स्तर की अपेक्षा 2.8 प्रतिशत पर रखी गई। इसी अवधि (अप्रैल-मार्च 2008-09) के दौरान राजस्व व्यय 33.2 प्रतिशत तक बढ़ा। इस अवधि के दौरान पूंजी व्यय में 24.1 प्रतिशत तक की स्पष्ट गिरावट पूर्ववर्ती वर्ष (2007-08) के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी के अधिग्रहण से सम्बन्धित लेनदेन के कारण है जो एक उच्चतर आधार प्रदान करता है। 2008-09 में (अन्तिम वास्तविक), कुल व्यय बजट अनुमान का 117.4 प्रतिशत था। इसी अवधि के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियां बजट अनुमान का 89.3 प्रतिशत थी। ये प्राप्तियां व्यय का केवल 62.5 प्रतिशत पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे 3,30,114 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा छूट गया। यह 2007-08 में 1,26,912 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे की तुलना में अधिक है। वर्ष 2008-09 के लिए राजस्व घाटा 2,47,046 करोड़ रुपए था। यह भी 2007-08 में 52,569 करोड़ रुपए के आंकड़े की तुलना में बहुत अधिक है। ऋण-भिन्न प्राप्तियां भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के अर्जन को छोड़ने के पश्चात 2007-08 की तुलना में 2008-09 में 0.03 प्रतिशत कम हो गई। यदि भारतीय स्टेट बैंक में भा.रि.बैं. की हिस्सेदारी के अधिग्रहण पर 34,308 करोड़ रुपए के एकबारगी व्यय को समायोजित किया जाता है तो 2008-09 कुल व्यय में वृद्धि 29.9 प्रतिशत थी। राजकोषीय प्रोत्साहन के भाग के रूप में करों में कटौती और वर्धित व्यय ने भी राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव डाला और 2008-09 में राजकोषीय स्थिति को खराब करने में योगदान किया, जिसमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.2 प्रतिशत (अन्तिम वास्तविक) के स्तर तक बढ़ गया। वर्तमान संकेतों के अनुसार, एक बार निकट भविष्य में वैश्विक वित्तीय संकट के दूर हो जाने पर, राजकोषीय सुदृढीकरण की प्रक्रिया को पुनः आरम्भ किया जा सकेगा।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत परिवर्तन	
		2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
वास्तविक क्षेत्र					
1.	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	4320.8 त्व.अ.	4933.2 सं.अ.	14.3 त्व.अ.	14.2 सं.अ.
	(ख) 1999-2000 के मूल्यों पर	3129.7 त्व.अ.	3339.4 सं.अ.	9.0 त्व.अ.	6.7 सं.अ.
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1993-94=100)	268.0	274.3	8.5	2.4
3.	शोक मूल्य सूचकांक (आधार 1993-94=100) ^क	226.7	228.6	7.8	0.8
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: औद्योगिक कामगार (2001=100)	137	148	7.9	8.0
5.	मुद्राआपूर्ति (एम3) (हजार करोड़ रुपए)	4017.6	4758.5	21.2	18.4
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात ^ख				
	(क) करोड़ रुपए	1012312	1305503	20.4	29.0
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	251439	287759	35.4	14.4
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात				
	(क) करोड़ रुपए	655864	766935	14.7	16.9
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	162904	168704	28.9	3.6
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)	-88535	-119055
9.	विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां				
	(क) करोड़ रुपए में	1196023	1230066	43.0	2.8
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर में	299230	241426	55.9	-19.3
10.	चालू लेखा शेष (मिलियन अमरीकी डालर में) (अप्रैल-दिसम्बर)	-15508	-36469
सरकारी वित्त साधन (करोड़ रुपए में) ^ग					
1.	राजस्व प्राप्तियां	541864	544651	24.8	0.5
2.	कर राजस्व (निवल)	439547	447726	25.2	1.9
3.	कर-भिन्न राजस्व	102317	96925	23	-5.3
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	170807	336818	14.6	97.2
5.	ऋणों की वसूली	5100	6158	-13.5	20.7
6.	अन्य प्राप्तियां	38795	546	7165	-98.6
7.	उधार और अन्य देनदारियां	126912	330114	-11	160.1
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	712671	881469	22.2	23.7
9.	आयोजना-भिन्न व्यय (10+12)	507589	606019	22.8	19.4
	जिसमें:				
10.	राजस्व खाता	420861	556521	13.1	32.2
	जिसमें:				
11.	ब्याज भुगतान	171030	190485	13.8	11.4
12.	पूंजी खाता	86728	49498	109.8	-42.9
13.	आयोजना व्यय (14+15)	205082	275450	20.7	34.3
	जिसमें:				
14.	राजस्व खाता	173572	235176	21.9	35.5
15.	पूंजी खाता	31510	40274	14.8	27.8
16.	कुल व्यय (9+13)	712671	881469	22.2	23.7
17.	राजस्व व्यय (10+14)	594433	791697	15.5	33.2
18.	पूंजी व्यय (12+15)	118238	89772	71.9	-24.1
19.	राजस्व घाटा (17-1)	52569	247046	-34.5	369.9
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	126912	330114	-11	160.1
21.	प्रारम्भिक घाटा (20-11)	-44118	139629	473	-416.5

त्व.अ. त्वरित अनुमान; सं.अ. संशोधित अनुमान

^क मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार (बिन्दुवार)

^ख सीमाशुल्क आधार पर: संशोधित आधार की तुलना में अनन्तिम आधार पर चालू वर्ष हेतु तुलनात्मक अध्ययन।

^ग लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े